भारत में आपातकाल घोषणा की 44वीं वर्षगांठ : आपातकाल विरोधी आंदोलन से आरएसएस की गद्दारी

शम्सुल इस्लाम

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25-26 जून, 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया था। यह 19 महीने तक लागू रहा। इस दौर को भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में काले दिनों के रूप में याद किया जाता है। इंदिरा गांधी का दावा था कि जयप्रकाश नारायण ने सशस्त्र बलों से कहा था कि कांग्रेस शासकों के अवैध आदेशों को नहीं मानें। इसने देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी और भारतीय गणतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया था।

आरएसएस का दावा है कि उसने इंदिरा गंधी द्वारा घोषित आपातकाल का बहादुरी के साथ मुकाबला किया और भारी दमन का सामना किया। बहरहाल, उस दौर के अनेक कथानक हैं, जो आरएसएस के इन दावों को झुठलाते हैं। यहां हम ऐसे दो दृष्टांतों का उल्लेख कर रहे हैं। इनमें से एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और विचारक प्रभाश जोशी हैं और दूसरे, पूर्व खुफिया ब्यूरो (आईबी) प्रमुख टीवी राजेश्वर हैं, जिनके द्वारा बताई घटनाओं का जिक्र हम यहां करेंगे। आपातकाल जिस समय घोषित किया गया था राजेश्वर आईबी के उप प्रमुख थे। राजेश्वर ने आपातकाल (जिसे राज्य का नंगा आतंकवाद कहना सही होगा) के उस दौर के बारे में बताया है किस तरह से आरएसएस ने इंदिरा गांधी के दमनकारी शासन के सम्मुख घुटने टेक दिए थे और इंदिरा गांधी एवं उनके पुत्र संजय गांधी को 20-सूत्रीय कार्यक्रम पूरी वफ़ादारी के साथ लागू करने का आश्वासन दिया था। आएसएस के अनेक %स्वयंसेवक% 20-सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के रूप में माफिनामें पर दस्तख़त कर जेल से छूटे थे।

इन तमाम गद्दारियों के बावजूद, ये आरएसएस वाले आपातकाल के दौरान उत्पीड़न के एवज में आज मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में उन लोगों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला लिया गया है जिन्हें आपातकालीन अवधि के दौरान एक महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था। और आरएसएस से जुड़े जो लोग इस दौरान एक माह से कम अवधि के जेल गए थे उन्हें बतौर 5000 रुपये पेंशन देना तय किया गया है। इस नियम में उन 'स्वयंसेवकों' का ख्याल रखा गया है, जिन्होंने केवल एक या दो महीने जेल में रहने के बाद घबरा कर दया याचिका पेश करते हुए माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस पेंशन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि लाभार्थी आपातकाल के पूरे दौर में जेल में रहा हो।

खास बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल में रहने वालों को मिलने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वालों में से एक भी आरएसएस का 'स्वयंसेवकों' नहीं है। यहां एक तथ्य गौरतलब है कि उन सैकड़ों कम्युनिस्ट युवकों का किसी को ख्याल तक नहीं है जिन्हें आपातकाल के इस दौर में नक्सलपंथी कह कर फर्जी मुठभेड़ों मे मार दिया गया था। यहां एक और रोचक तथ्य है कि आरएसएस के हिंदुत्व सह-यात्री शिवसेना ने खुले आम आपातकाल का समर्थन किया था।

प्रभाष जोशी का लेख अंग्रेजी साप्ताहिक तहलका में आपातकाल की 25 वीं वर्षगांठ पर छपा था । उनके अनुसार आरएसएस के आपातकाल विरोधी संघर्ष में सहभागिता को लेकर उस दौर में भी मन ही मन हमेशा एक किस्म का संदेह, उसके साथ कुछ दूरी, विश्वास की कमी का भाव था। उन्होंने आगे बताया, उस समय के आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने संजय गांधी के कुख्यात 20-सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में सहयोग करने हेतु इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। यह है आरएसएस का असली चरित्र...आप उनके काम करने के अंदाज़ और तौर तरीकों को देख सकते हैं। यहां तक कि आपातकाल के दौरान, आरएसएस और जनसंघ के अनेक लोग माफीनामा देकर जेलों से छूटे थे। माफी मांगने में वे सबसे आगे थे। उनके नेता ही जेलों में रह गए थे- अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, यहां तक कि अरुण जेटली। आरएसएस ने आपातकाल लागू होने के बाद उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं किया। तब, भाजपा आपात काल के खिलाफ संघर्ष की याद को अपनाने की कोशिश क्यों कर रही है?

प्रभाष जोशी के निष्कर्ष के अनुसार, वे कभी संघर्षशील शक्ति न तो रहे हैं न ही वे कभी संघर्ष के प्रति उत्सुक रहनों वालों में से हैं। वे बुनियादी तौर पर समझौतापरस्त रहे हैं। वे कभी भी सही मायने में सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वालों में नहीं रहे हैं।

टी.वी. राजेश्वर सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश और सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया- द क्रूशियल इयर्स' (हार्पर कॉलिन्स) में, इस तथ्य की पुष्टि की है कि वह (आरएसएस) न केवल इसका (आपातकाल का) समर्थन कर रहा था, वह श्रीमती गांधी के अलावा संजय गांधी के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता था। राजेश्वर ने मशहूर पत्रकार, करन थापर के साथ एक मुलाकात में खुलासा किया कि देवरस ने गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री आवास के साथ संपर्क बनाया और देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार ने जो सख़्त कदम उठाए थे उनमें से कई का मजबूती के साथ समर्थन किया था। देवरस श्रीमती गांधी और संजय से मिलने के इच्छुक थे। लेकिन श्रीमती गांधी ने इनकार कर दिया।

राजेश्वर की पुस्तक के अनुसार, आरएसएस, एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, आपातकाल के समय इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन इसके प्रमुख बाला साहेब देवरस...ने लागू आदेशों और देश में अनुशासन को लागू करने के लिए सरकार के अनेक आदेशों का मजबूती के साथ समर्थन किया था। संजय गांधी के परिवार नियोजन अभियान और इसे विशेष रूप से मुसलमानों के बीच लागू करने के प्रयासों को देवरस का भरपूर समर्थन हासिल था।

राजेश्वर ने यह तथ्य भी साझा किया है कि आपातकाल के बाद भी संघ (आरएसएस) ने आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को अपना समर्थन विशेष रूप से व्यक्त किया था। यह खास तौर पर गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो अब आरएसएस के प्यादे हैं के अनुसार भी आपातकाल की अवधि में, आरएसएस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष के साथ गद्दारी की थी।

आरएसएस अभिलेखागार में समकालीन दस्तावेज प्रभाष जोशी और राजेश्वर के कथन की सत्यता प्रमाणित करते हैं। आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक, मधुकर दत्तात्रय देवरस ने आपातकाल लगने के दो महीने के भीतर इंदिरा गांधी को पहला पत्र लिखा था। यह वह समय था जब राजकीय आतंक चरम पर था। देवरस ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त, 1975 की शुरुआत ही इंदिरा की प्रशंसा के साथ इस तरह की।

मैंने 15 अगस्त, 1975 को रेडियो पर लाल किले से देश के नाम आपके संबोधन को जेल (यारवदा जेल) में सुना था। आपका यह संबोधन संतुलित और समय के अनुकूल था। इसलिए मैंने आपको यह पत्र लिखने का फैसला किया।

इंदिरा गांधी ने देवरस के इस पत्र को जवाब नहीं दिया। देवरस ने 10 नवंबर, 1975 को इंदिरा को एक और पत्र लिखा। इस पत्र की शुरुआत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिए गए निर्णय के लिए बधाई के साथ की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको चुनाव में भ्रष्ट साधनों के उपयोग का दोषी मानते हुए पद के अयोग्य करार दिया था। देवरस ने इस पत्र में लिखा,

सुप्रीम कोर्ट के सभी पांच न्यायाधीशों ने आपके चुनाव को संवैधानिक घोषित कर दिया है, इसके लिए हार्दिक बधाई। गौरतलब है कि विपक्ष का दृढ़ मत था कि यह निर्णय कांग्रेस के द्वारा मैनेज्ड था। देवरस ने अपने इस पत्र में यहां तक कह दिया कि आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ अन्यथा जोड़ दिया गया है। सरकार ने अकारण ही गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन के साथ भी आरएसएस को जोड़ दिया है...संघ का इन आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है ...

इंदिरा गांधी ने क्योंकि देवरस के इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, आरएसएस प्रमुख ने विनोबा भावे के साथ संपर्क साधा, जिन्होंने आपातकाल का आध्यात्मिक समर्थन और इंदिरा गांधी का पक्ष लिया था। देवरस ने अपने पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1976 में, आचार्य विनोबा भावे से गिड़गिड़ाते हुए आग्रह किया कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के लिए वे इंदिरा गांधी को सुझाव दें। आचार्य विनोबा भावे ने भी पत्र का जवाब नहीं दिया, हताश देवरस ने एक और पत्र लिखा जिस पर तिथि भी अंकित नहीं है। उन्होंने लिखा-

अखबारों में छपी सूचनाओं के अनुसार प्रधान मंत्री (इंदिरा गांधी) 24 जनवरी को वर्धा पवनार आश्रम में आपसे मिलने आ रही हैं। उस समय देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में उनकी आपके साथ चर्चा होगी। मेरी आपसे याचना है कि प्रधानमंत्री के मन में आरएसएस के बारे में जो गलत धारणा घर कर गई है आप कृपया उसे हटाने की कोशिश करें ताकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सके और जेलों में बंद आरएसएस के लोग रिहा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति और विकास में सभी क्षेत्रों में अपना योगदान कर सकें।

आरएसएस का पुराना चलन है कि वह हुक्मरानों के पाले में रहता आया है, निरंकुश शासन का हिमायती रहा है। यही वजह है कि आरएसएस के किसी भी नेता और स्वयं सेवक ने औपनिवेशिक गुलामी के दौर में जंगे आज़ादी में कोई शिरकत नहीं की। सच यह है कि आरएसएस क्रूर सर्वसत्तावादी अधिनायक तंत्र की पुजारी है। आरएसएस के सबसे प्रमुख विचारक, संगठन के दूसरे प्रमुख, गोलवलकर ने बहुत पहले 1940 में ही घोषित कर दिया था, आएसएस एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित इस महान भूमि के प्रत्येक अंचल को हिंदुत्व की ज्वाला से रोशन कर रहा है।

हाल ही में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नए स्वयंसेवकों के दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। प्रणब मुखर्जी की गिनती आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च कांग्रेसी नेताओं में होती है और शाह आयोग ने भी आपातकाल की ज्यादतियों के लिए उन्हें प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना था।

आरएसएस के प्रधान कार्यालय पर प्रणब का सत्कार करते हुये जाहिर है आरएसएस को किसी भी तरह की लज्जा नहीं आयी। आरएसएस की त्रासदी यह है कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक कायम है। यही उसकी विवशता है। हालांकि वह नग्न तानाशाही का कट्टर हिमायती है परंतु उसे अपनी इस असलियत को छुपाने के लिए मुखौटे लगाने पड़ते हैं।

आपातकाल के दौरान आरएसएस ने आखिर क्यों मांगी थी इंदिरा गांधी से माफी!

कम ही लोगों को पता होगा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि संघ परिवार को कांग्रेस की सर्वेसर्वा और उस वक्त पीएम की कुर्सी पर बैठी देश की सबसे मजबूत महिला इंदिरा से माफी मांगने की नौबत आ गई?

साल 1987 में लिखित पुस्तक द ब्रदरहुड इन सैफ्रन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू रिवाइलिज्म को 28 साल बाद नए सिरे से लिखे जाने की आरएसएस की योजना है, जिसमें इसके कारणों का खुलासा किए जाने की संभावना भी है। पुस्तक में आपातकाल के दौरान संघ के तीसरे सरसंघचालक बालासाहेब देवरस की ओर से इंदिरा से माफी मांगे जाने की वजह का खुलासा किया जाएगा। 28 साल पहले अमेरिकी विदेश विभाग में काम करने वाले वॉल्टर के. एंडरसन और संघ से नजदीकी रिश्ता रखने वाले श्रीधर डामले ने यह पुस्तक लिखी थी। लेकिन अब इसे एंडरसन ने जॉन्स होपकिंस और डामले के साथ दोबारा लिखने की योजना बनाई है। डामले फिलहाल अमेरिका के शिकागो में एक स्वतंत्र शोधकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुस्तक के नए संस्करण में संघ के तीसरे सरसंघचालक बालासाहेब देवरस की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

बालासाहेब देवरस

इंदिरा गांधी से माफी मांगने को लेकर डामले ने कहा कि यह संघ की रणनीति का हिस्सा था। यहां तक कि वाजपेयी से भी माफी मांगने को कहा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बताया था, "मैं बिना अनुमति के कुछ भी नहीं कर रहा हूं।" इस किताब में पहली बार एकनाथ रानाडे का भी जिक्र किया जाएगा। रानाडे ने कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल की स्थापना की थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी भी उस मेमोरियल को देखकर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकी थीं। गौरतलब है कि संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी के कार्यकाल में रानाडे छह साल तक संघ के सरकार्यवाह के पद पर भी रहे थे।